

57

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वांतियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा म.पु.



Rs. 250/- 16

Rs. 30/-

- 1- वसंतलाल पिता श्री बाल्मीक प्रसाद मिश्रा
- 2- राधिका प्रसाद मिश्रा पिता श्री बाल्मीक प्रसाद मिश्रा
- 3- सुरज प्रसाद मिश्रा पिता श्री बाल्मीक प्रसाद मिश्रा
- 4- राजेश प्रसाद मिश्रा पिता श्री बाल्मीक प्रसाद मिश्रा
- 5- कैलाश मिश्रा पिता श्री वेदर प्रसाद मिश्रा

सभी निवासी ग्राम बैजनाथ, तहसील हुजूर, जिला रीवा म.पु.

----- आवेदक गण

बनाम

- 1- जगन्नाथ गडीरया पिता पिपारे गडीरया, सार्जन बैजनाथ तह. हुजूर थाना धारेहटा जिला रीवा म.पु.

----- अनावेदक

श्री. राम प्रताप द्विवेदी  
द्वारा आज दिनांक 6-6-16  
प्रस्तुत किया गया।

सिद्ध  
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक महोदय  
सर्किट बन्कुहयां, वा. वत प. क्र. 73/अ-12/15 -  
2016 आदेश दिनांक 30.5.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.पु. क्र. राजस्व  
सीहता 1959 हर्षणी.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1:- यह कि विधान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि, प्रक्रिया एवं  
नैसर्गिक न्याय के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

राम प्रताप द्विवेदी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 5250-दो/15

जिला - रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-7-17	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। चूंकि आवेदक आवेदक अभिभाषक पिछली पेशी पर उपस्थित थे तथा इस पेशी पर अनुपस्थित है इसलिए प्रकरण अदम पैरवी में खारिज होना चाहिए चाहिए, परन्तु न्याय प्रदान करने की दृष्टि से प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमो एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जा रहा है। आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक सर्किल बनकुइयां के प्रकरण क्रमांक 73/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 30-5-16 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। सीमांकन पंचनामों से आवेदक का सीमांकन कार्यवाही से प्रभावित होना प्रथमदृष्टया परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी पर विचार किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जी है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	<p>(एस0एस0 अली) सदस्य</p>